शोध मंथन Vol. XVI No.2 Apr.- June. 2025 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X, Impact Factor 8.877 (SJIF)
https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.31

पाकिस्तान के लोकतंत्र में मुस्लिम लीग की भूमिका

प्राप्तिः 20.03.2025
स्वीकृतः 24.04.2025

31

डॉ. पूजा
असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीतिक विभाग)
भगिनी निवेदिता कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
ईमेलः poojascholar26@gmail.com

सारांश

पाकिस्तान, एक राष्ट्र के रूप में अंग्रेजों के भारत को सत्ता हस्तांतरण, एवं भारत विभाजन के उपरांत अस्तित्व में आया। पाकिस्तान अपने निर्माण के समय से ही कई प्रकार की चुनौतियों से घिरा हुआ था जिसमें, राष्ट्र निर्माण, पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में बनाए रखना, भाषाई विभिन्नता, राजनीतिक–आर्थिक संघर्ष आदि शामिल है। शुरुआत से ही पाकिस्तान के लोकतंत्र में कई उतार–चढ़ाव आये। जिसमें पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। पाकिस्तान जैसे नए राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विकसित करने के लिए आवश्यक राजनीतिक संस्थाओं की कमी थी। पाकिस्तान आंदोलन प्रमुखतः मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतो के मुस्लिमों का आन्दोलन था तथा यह उन क्षेत्रों में कमजोर था जो नए राष्ट्र का हिस्सा बने। पाकिस्तान के निर्माण के समय मुस्लिम लीग एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल था। मुस्लिम लींग केवल बंगाल तथा सिंध में ही सत्ता में थी। पाकिस्तान के गठन के बाद जल्द ही सत्तासीन मुस्लिम लींग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान में राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना नहीं हो सकी तथा देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विकसित नहीं हो पायी।

मुख्य बिंदु

पाकिस्तान, लोकतंत्र, राजनैतिक दल, मुस्लिम लीग।

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद से पाकिस्तान की राह आसान न रही, जिन्ना एवं लियाकत अली की मृत्यु के बाद पाकिस्तान लोकतंत्र की जगह सैनिक शासन के द्वारा शासित हुआ। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें 1947–1958, 1971–77, 1988–99, 2008 से वर्तमान तक रही, बाकी आने वाले समय में सैनिक शासन स्थापित रहा। जब से पाकिस्तान, एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया तो विश्व के समाज में पाकिस्तान को लेकर कई तरह की धारणायें रही है, कोई इसे असफल देश या (फेल्ड स्टेट), तथा कोई इसे विश्व की सबसे खतरनाक जगह मानता है। फ्रेंच दार्शनिक बर्नाड हेनरी लेवी पाकिस्तान को अत्यधिक अपराध के राष्ट्र की संज्ञा देते है।[1]

मुहम्मद अली जिन्ना तथा मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश भारत को हिन्दू व मुस्लिम राष्ट्रों में विभाजित करने की मांग वाले आंदोलन का नेतृत्व किया और 1947 ई. में पाकिस्तान के गठन के बाद लीग पाकिस्तान की प्रमुख राजनीतिक दल बन गई। इस साल ही इसका नाम बदलकर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में आधुनिक राजनीतिक दल के रूप में लीग उतने कारगर ढंग से काम नहीं कर सकी, जैसा यह ब्रिटिश भारत में जन–आधारित दबाव गुट के रूप में काम करती थी और इस तरह से धीरे–धीरे इसकी लोकप्रियता व संगठन की क्षमता घटती चली गई। 1954 ई. चुनावों में 'मुस्लिम लीग' ने पूर्वी पाकिस्तान में सत्ता खो दी और इसके तुरंत बाद ही पार्टी ने पश्चिमी पाकिस्तान (वर्तमान पाकिस्तान) में भी सत्ता खो दी। 1960 के दशक के अंत में पार्टी विभिन्न गुटों में बट गई और 1970 ई. के दशक तक यह पूरी तरह गायब हो चुकी थी। इस प्रकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग 1970 के बाद पाकिस्तान के राजनीति में प्रभावी हो गया। आधुनिक पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नाम से कई दल कार्य करते है और सबसे रोचक बात यह है कि सभी दल अपने आपको जिन्ना और लीग से जोड़कर देखते है।

कन्वेंशनल मुस्लिम लीग

इस दल की स्थापना पाकिस्तान में सैनिक शासन के दौरान हुई। पाकिस्तान के कुछ नेता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नीति से अलग अपनी राजनीति की स्थापना करना चाहते थे। अयूब खान ने 1958 में पाकिस्तान की सत्ता संभाली। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। एक पुराने और अनुभवी राजनीतिज्ञ अकरम खान के घर में 1962 में एकत्र हुए, मुस्लिम लीग के कई पूर्व नेताओं जो कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय नहीं थे, एक दल बनाने का निर्णय लिया जिसका नाम कन्वेंशनल मुस्लिम लीग रखा गया।

23 मई, 1963 को जनरल एम. अयूब खान ने 'कन्वेंशनल लीग' में शामिल होने की घोषणा की। 24 दिसम्बर, 1963 को अयूब खान को कन्वेंशनल लीग के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। उन्होंने मुस्लिम लीग के टिकट पर 1965 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। जब उन्होंने 1965 के राष्ट्रपति चुनावों में भाग लिए तो उनके समर्थकों ने विशेष रूप से पूर्वी पाकिस्तान में अधिक से अधिक शक्ति के साथ पी.एम.एल पुननिर्माण करने का प्रयास किया। लीग का उद्देश्य पाकिस्तान को एक आदर्श राज्य बनाना था। एम. अयूब खान देश के विकास के लिए बैंकिंग और उद्योगों, बीमा व्यापार राष्ट्रीयकरण के नीति का समर्थन कन्वेंशनल मुस्लिम लीग ने किया।

पी.एम.एल में अध्यक्ष का बहुत वर्चस्व रहता था, पार्टी संगठन के प्रमुख केन्द्रीय निकायों के सदस्य निर्वाचित नहीं थे, लेकिन अयूब खान द्वारा मनोनीत किये गए थे। जब अयूब इस दल में शमिल हुए तो कई महत्वपूर्ण नेताओं सहित कई जमींदारों ने भी इस दल को अपना समर्थन दिया और यह पार्टी एक मजबूत और देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इस दल ने देश के महत्वपूर्ण सीटों पर कब्ज़ा किया। सन् 1964–65 के चुनावों के बाद राजनीतिक दलों ने मुख्य राजनीतिक ब्लाक का गठन किया जिसमें एक तो खुद सत्तारूढ़ मुस्लिम लीग था, और दूसरे कुछ विपक्षी दल थे। सन् 1965 के चुनावों में विपक्षी पार्टियाँ बुरे तरीके से हार गई। सत्तारूढ़ पार्टी ने 'कन्वेंशनल लीग' की स्थिति को मजबूत बनाया और राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा, राष्ट्रपति चुनाव

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.31

में अपनी स्थिति मजबूत की। पूर्वी पाकिस्तान में पार्टी इतनी अप्रभावी नहीं थी। पूर्वी पाकिस्तान में यह संगठन बहुत कमजोर था।[2]

पाकिस्तान में दलीय प्रणाली

पाकिस्तान में स्वतंत्रता के समय से ही बहुदलीय (Multiparty) प्रणाली है।[3] हालांकि अधिकतर समय में सैनिक शासन ही रहा है। सांस्कृतिक विविधता, बहुलवाद और विचारधारा ने बहुदलीय प्रणाली को आकार दिया। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग में वर्तमान में 250 दल नामजद है।[4] पाकिस्तान में लोकतंत्र की अवधि बहुत कम समय की रही है, क्योंकि सैनिक शासन के कारणवश ज्यादातर राजनैतिक दलों को फलने–फूलने का मौका नहीं मिल पाया। पाकिस्तान में गठबंधन की राजनीति को सन् 1988 के बाद हुए सभी चुनावों में देख सकते है।

पाकिस्तान में राजनीतिक दलों अस्तित्व बहुत पुराना है। पाकिस्तान की राजनीति में दल वह मुकाम हासिल नहीं कर सका जो एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक होते है, लेकिन जितनी भी पाकिस्तान की राजनीति में दलों को कार्य करने का अवसर मिला, उन दलों ने अपनी भूमिका का निर्वहन करने में पुरजोर कोशिश हासिल की। पाकिस्तान की राजनीति में दो दलों के महत्व को विशेष रूप से देख सकते हैः एक राष्ट्रीय दल और दूसरा क्षेत्रीय दल। पाकिस्तान में बहुत कम ही दलों को राष्ट्रीय दल होने का श्रेय प्राप्त है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि ज्यादातर दल किसी विशेष प्रांत तक सीमित होते है और वे अपनी राष्ट्रव्यापी पहुँच नहीं बन पाते है।[5]

दलीय प्रणाली का सिद्धांत

किसी देश की आर्थिक, सामाजिक उत्थान, जनकल्याण परियोजना का क्रियान्वयन के लिए एक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण एवं उसके संचालन में दलों का अपना अलग ही महत्व है। दल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का केन्द्रीय भाग होता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था पर विचार रखते हुए डगलस वी. वर्नी कहते है कि सरकार की संरचना की ओर ध्यान देने के बजाय लेखक सहभागिता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया रहते है जिसे कभी–कभी राजनीतिक प्रक्रिया कह सकते है।[6] हर राजनीतिक व्यवस्था की अपनी दलीय प्रणाली है, चाहे वह एक दलीय, द्वि–दलीय तथा बहुदलीय व्यवस्था हो। परन्तु कुछ देश जिसे सऊदी अरब एवं थाईलैंड इसके प्रमुख अपवाद के रूप में शामिल है। दलीय प्रणाली के संदर्भ में सारटोरी ने कुछ दलों का अध्ययन करने की सलाह दी है। जैसे– वे दल जो मतों को बढ़ाने में रूचि नहीं रखते हो दूसरा, वे दल जो मतों की संख्या बढ़ाने के लिए अपनी नीतियों का समर्पण न करें।[7]

मुख्य राजनीतिक दल

पाकिस्तान में बहुत कम राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी दर्जा प्राप्त है इसका प्रमुख कारण राजनीतिक दलों का किसी विशेष स्थान या एक या दो प्रांतो तक सीमित होना है। सन् 1990 के दशक में पाकिस्तान में लोकतंत्र नाजुक दौर से गुजर रहा था, जो तत्काल सेना के शासन से मुक्त हुआ था और जनतांत्रिक सरकार के निर्माण की तरफ उन्मुख था। उस दौर में गठजोड़ की सरकार की संकल्पना का विकास हुआ था जो बहुदलीय प्रणाली में होती है। सन् 1988, 1990 और 1993 के चुनावों में भंगुर बहुमत ने राजनीतिक दलों का गठबंधन की सरकार की सरकार के लिए

मजबूर किया। चुनाव हो या चुनाव के बाद का गठजोड़ हो उसमें कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी, लोगों के मतदान के केंद्र में रहती थी। अभी तक पी.पी.पी और पी.एम.एल (एन), एक दूसरे के साथ सीधे राजनीतिक प्रतियोगिता में रहते है।[8]

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) का उदय

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) का नाम पाकिस्तान के राजनीति में प्रमुखता से लिया जाता है। पाकिस्तान में स्थापित मुस्लिम लीग (नवाज), 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से भिन्न है क्योंकि उसकी स्थापना स्वतंत्रता आन्दोलन में योगदान के लिए हुई थी।[9] जिसने भारत से पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुआ तो भारतीय मुस्लिम लीग का नाम परिवर्तित कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कर दिया गया, जिसके प्रमुख नेता जिन्ना एवं लियाकत अली थे। पाकिस्तान में जिन्ना एवं लियाकत अली के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने अपनी राष्ट्र निर्माण योजना को साकार रूप देने का प्रयास किया। परन्तु ज्यादा दिनों तक दोनों नेताओं के जीवित ने रहने के कारण पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपनी नीतियों का क्रियान्वयन न कर सकी। अभी लोकतंत्र के बीज फूटे ही थे कि पाकिस्तान की राजनीति में सैन्य प्रशासन की काली छाया व्याप्त हो गयी और लोकतंत्र को करारा झटका लगा, जब सन् 1958 में जनरल अयूब ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया।[10] सैनिक शासन के लागू होने के कारण पाकिस्तान मे लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया कमजोर दिखती प्रतीत हुई। पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने अपने शासन को वैध साबित करने के लिए राजनीतिक दलों का सहारा लिया। जो भी शासक (सैन्य) आता वह अपने आपको मुस्लिम लीग की भूमिका से जोड़कर देखता था। सन् 1962 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग स्थापित हुआ जिसे अयूब खान ने स्वयं बनाया। अयूब ने 'आधारीय लोकतंत्र'[11] की परिकल्पना दी जिसके कारण उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मजबूत करने का प्रयास किया।[12] नवाज एक प्रखर नेता के रूप में पाकिस्तान की राजनीति में उभर कर सामने आए। नवाज शरीफ के बारे में यह सत्य कथन है कि, शरीफ की प्रमुख विशेषता थी कि उनका सम्पर्क पाकिस्तान के दो शक्तिशाली सत्ता के स्थापनाकारी से रहा जिनमें एक राष्ट्रपति इश्क खान एवं उनकी विवेकाधिक शक्तियाँ तथा दूसरी आर्मी, जो पाकिस्तान की अंतिम मध्यस्थता के रूप में शामिल रही है।[13]

सन् 1988 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की शुरुआत, मोहम्मद जुनेओ खान, फिदा खान एवं नवाज शरीफ के प्रयास के परिणामस्वरूप हुई। यह पाकिस्तान की राजनीति का वह दौर था जब जिया के असामयिक निधन एवं लोकतंत्र की बहाली का अगाज हुआ था। पाकिस्तान एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली एवं पी.पी.पी की जीत ने पाकिस्तान की राजनीति को एक नयी आशा की किरण दिखायी।[14]

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) का उद्देश्य

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) का प्रमुख उद्देश्य आधुनिक पाकिस्तान निर्माण जिसमें इस्लाम केन्द्रीय तत्व है। दल की धार्मिकता बस इसी बात से पता चलती है कि पूरे ब्रह्मांड पर संप्रभुता सर्वशक्तिमान अल्लाह के अंतर्गत आता है, और उसके द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर पाकिस्तान के लोगों को कार्य करने का अधिकार है। अल्लाह के ऊपर निर्भरता एक पवित्र विश्वास

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.31

है।[15] अतः यह पार्टी धार्मिक रुढ़िवादी (इस्लाम के संदर्भ में) सामाजिक रुढ़िवादी तथा नव रुढ़िवादी, जैव रुढ़िवादी तथा पर्यावरण रुढ़िवादी नीति पर आधारित रही है।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) का लक्ष्य ज्ञान के आधार पर पाकिस्तान में राष्ट्र निर्माण आधुनिक तकनीकों एवं उपागमों से अर्थव्यवस्था, उच्च कोटि का मानवीय स्त्रोत, लोकतंत्र का सुदृढ़िकरण, सुशासन, न्याय, अवसर की समनता, रोजगार, सृजन, गरीबी उन्मूलन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की प्रमुख समस्या के रूप में बेरोजगारी को माना है और यह तेजी से औद्योगीकरण से ही हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ग्रामीण औद्योगीकरण और कृषि आधारित उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पर विचार कर रही है और साथ ही विनियमन के प्रति प्रतिबद्ध है।[16]

पार्टी का ध्वज, चुनाव चिन्ह

दल का अधिकारिक नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज (अनुच्छेद, 1) है। इस दल के संविधान ने दल के लिए ध्वज का रंग, आकार के बारे में उल्लेख किया है। दल के ध्वज का रंग हरा होगा। जिसमें अर्द्धचंद के बीच एक तारा होगा। (अनुच्छेद,3) यह दलीय ध्वज उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दल का ध्वज था। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) को 'बाघ' चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया है।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) का घोषणा पत्र

पाकिस्तान में 3 फ़रवरी 1997 को आम चुनाव कराए गए, इस चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी घोषणा पात्र जारी किये। सभी दलों ने इस चुनाव में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा पर अपनी चिंता व्यक्त की। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एवं पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के बीच था। पी.एम.एल. ने चुनाव के पूर्व अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए, आवामी नेशनल पार्टी एवं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (शाहिद–भुट्टो) से गठबंधन किया। नवाज ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में राष्ट्र के सभी नागरिकों के आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता के लिए काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।[17]

नवाज के दल की चुनावी घोषणा पत्र में पाकिस्तान की सम्प्रभूता अखंडता की रक्षा, इस्लामिक जीवन के मूल्यों को बनाये रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया साथ–साथ कृषि व उद्योगों के तीव्र गति से विकास और एक आधुनिक पाकिस्तान के निर्माण पर जोर देता है। इस चुनाव में नवाज ने आर्थिक स्थिति के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अपनी वचनबद्धता जतायी। नवाज के पाकिस्तान में आर्थिक सुधारों की कमी को महसूस किया। पी.एम.एल.एन ने आर्थिक सुधारों के साथ, कृषि की दशा में सुधार, बेरोजगारी, उद्योग एवं व्यापार का विकास, वित्तीय संस्थाओं में सुधार एवं उनका पुनर्गठन, सरकारी पदों पर ईमानदारी एवं निष्ठावान व्यक्तियों की नियुक्ति, पाकिस्तान स्टेट बैंक की स्वायत्तता को सुनिश्चित किया जाए।

नवाज की पार्टी ने 3 फ़रवरी को चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस पत्र में दल ने मुद्रा स्फ्रीति की दर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक नीतियों की कमी तथा कर को एकत्रित करने वाली प्रणाली में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने के आवश्यकता पर बल दिया। इस चुनावी घोषणा

पत्र में नवाज की पार्टी ने देश के निर्यात में 20 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि का लक्ष्य रखा साथ ही देश का सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को दस वर्षों में दो गुने तक पहुचाने का वादा किया। दल ने देश के विधुत संबंधी समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया। दल ने जनता से वादा किया कि सत्ता में आते ही ऊर्जा नीति का नवनीकरण किया जायेगा जिससे विधुत उत्पाद की क्षमता को बढ़ाया जाए साथ ही दल ने उत्पाद की दर को न्यूनतम करने की बात दोहराई।[18]

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के सत्ता का काल

पाकिस्तान में 11 वर्षों तक सैनिक शासन रहा और जनरल किया उल हक़ ने 1977 से लेकर 1988 तक शासन किया। पाकिस्तान में लोकतंत्र की वापसी जनरल जिया उल हक़ के निधन एवं पाकिस्तान में निर्वाचन के बाद हुआ। बहुत वर्षों के बाद पाकिस्तान की जनता ने सरकार के निर्माण में अपनी भागीदारी का निर्वाचन में मत देकर निभाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) ने पाकिस्तान की राजनीति में दो बार सत्ता पर अपना अधिकार किया। नवाज शरीफ के नेतृत्व में प्रथम बार 1990 में सत्ता में आयी, जब राष्ट्रपति ने बेगम बेनजीर भुट्टो को सत्ता से निष्काषित किया। अतः हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के कार्यकलाप को दो वर्गों में देख सकते हैं–

प्रथम कार्यकाल (1990–1993)

नवाज शरीफ प्रथम बार 1990 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपनी पार्टी एवं कुछ अन्य दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया, जिसका नाम इस्लामिक ज्होरी इत्तेहाद था। नवाज की सरकार के सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ थी, पहला पाकिस्तान की जनता को एक स्थायी सरकार देना, दूसरा पाकिस्तान की जनता की आशाओं को पूरा करना, तीसरा सबसे प्रमुख सेना एवं राष्ट्रपति के साथ तालमेल रखना। नवाज ने एक कुशल शासक की तरह तत्कालीन समस्याओं से निपटने का प्रयास किया। कुकरेजा इन्हीं बातों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि, जब वह अपने गठबंधन के साथियों के साथ सत्ता में आये तो वह सेना के व्यवसायिक हित एवं सेना के प्रमुख अधिकारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को लेकर बहुत सचेत रहे क्योंकि सेना पाकिस्तान में सत्ता की कुंजी है।[19]

नवाज ने अपनी तरफ से यह प्रयास किया कि सेना के साथ सरकार का मधुर सम्बन्ध बना रहे, लेकिन सेना एवं राष्ट्रपति के साथ मधुर संबंध रहने के बावजूद इन सभी परिस्थितियों से लाभ न सके तभी तो कुकरेजा ने मुसाहिद हुसैन के हवाले से यह कहा है कि–'नवाज शरीफ के कद में निरंतर हास के गवाह रहे, नृजातीय संघर्ष एवं उनकी स्थानीय केंद्र सरकार की नीति'। कुकरेजा के इस कथन का आशय है कि नवाज ने अपनी सत्ता के दौरान हुए नृजातीय संघर्ष के लिए स्पष्ट नीति को बनाने में कोई कारगर सफलता नहीं मिली।[20] अतः नवाज की सरकार के कार्यकाल के प्रमुख राजनीतिक कार्यकलापों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता हैः–

आर्थिक नीतियाँ

नवाज जब सत्ता में आये तो उन्होंने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रति अपनी वचनबद्धता जतायी। नवाज के, सरकार में आते ही अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना उनके पृष्ठभूमि की तरफ भी इंगित करता है क्योंकि उनका संबंध एक व्यवसायी परिवार से था। व्यवसायी घराने से संबंध रखने के कारण, शरीफ एवं उनकी सरकार उदारीकरण के प्रति दृढ़ निश्चय रहा। सरकार का पूरा ध्यान निजीकरण एवं निर्यात पर था।[21]

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.31

विनियमन

नवाज पाकिस्तान के उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने आर्थिक विकास को अपने नीतियों के केंद्र बिंदु में रखा था। अर्थव्यवस्था में ध्यान देने के साथ ही नवाज ने अर्थव्यवस्था के आधार जैसे मुक्त बाजार की तरफ ध्यान केंद्रित किया, जिससे निजी क्षेत्रों एवं विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाए।[22]

द्वितीय कार्यकाल (1997–1999)

सन् 1997 में हुए निर्वाचन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) ने बहुत बड़ी विजय हासिल की, 277 सीटों में से 177 सीटों (राष्ट्रीय असेम्बली) तथा अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ चार प्रान्तों में सरकार बनायीं। यह विजय 1971 के जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद सबसे अहम एवं महत्वपूर्ण विजय रही। नवाज शरीफ की इस जीत ने उनकी प्रसिद्धी और बढ़ा दी। उनकी इस विजय से लोगों को यह आशा थी कि एक रुढ़िवादी होने के बावजूद की नवाज शरीफ एक स्थायी शासन देंगे एवं जनहित एवं लोकोन्मुख नीति लायेंगे। सत्ता में आते ही उन्होंने कुछ संवैधानिक संशोधन करने का प्रयास किया। उनका दूसरा कार्यकाल एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक सरकार के लिए याद रखा जायेगा। 1 अप्रैल 1977 को प्रधानमंत्री ने एक बिल प्रस्तुत किया जो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ को सीमित करने तथा सरकार को भंग करने की शक्ति का निर्मुलिकरण था। इसको 13 वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण विधेयक लाया गया जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय या प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों को पार्टी नेतृत्व हटा सकती है यदि वह दलबदल करे या सरकार के हित का उल्लघन करें। (सईद 1998: 119)

आर्थिक नीतियाँ

नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने अर्थव्यवस्था को संकट से उबारना सबसे बड़ी चुनौती थी। सन् 1997 में पाकिस्तान, असंतुलित व्यापार, धीमी आर्थिक वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज, वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, रुपये की गिरती कीमते आदि प्रमुख आर्थिक समस्याएं थी, जिसे नवाज की सरकार को हल करना था। सरकार के आने के बाद नवाज सरकार ने कई कदम उठाये, जिसमें करों में वृद्धि की गई जिससे कर्ज को कम किया जा सके, लेकिन यह आवश्यक कर्ज को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सामान्य जनता विशेष रूप से कृषक, किसी प्रकार के अतिरिक्त कर के भार को सहने के स्तर पर न थे। केन्द्रीय सरकार ने प्राकृतिक स्त्रोतों से प्राप्त राजस्व में प्रांतों की हिस्सेदारी को कम करने की नीति बनाई।[23]

संदर्भ

1. Stephen Philip Cohen, Idea of Pakistan, (New Delhi: Oxford University Press, 2005), Pg. 02
2. पाकिस्तान निर्वाचन आयोग, पाकिस्तान के आम चुनाव (1964–65)।
3. यहाँ बहुदलीय से तात्पर्य है दो दलों से अधिक दल अर्थात् पाकिस्तान के प्रारंभिक समय में दलों की मौजूदगी तो थी, परन्तु कुछ ही दलों की प्रभावगी अन्य दलों से ज्यादा थी। जैसे–स्वतंत्रता के समय कई दल थे परन्तु पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही ज्यादा हावी थी।
4. Pakistan Election Commission: list of Political Parties

5. Story of Pakistan, http://storyofpakistan.com/establishment-of-all-india-muslim-league. 26.07.2013
6. Douglas V. Verney, The Analysis of Political Systems, London: Rutledge, 1959, Pg. 01
7. Giovanni Sartori, Parties and Party System a framework for analysis, London: Cambridge University Press), Pg. 327
8. पाकिस्तान निर्वाचन आयोग, पाकिस्तान के आम चुनाव (1988–1977), http://ecp.gov.pk/GE/1988-1977/Results8897.aspx ,2013
9. Story of Pakistan, http://storyofpakistan.com/establishment-of-all-india-muslim-league. 26.07.2013
10. Hasan Akskari Rizvi, Military State and Society in Pakistan, London: Macmillan Press, 2000, Pg. 84.
11. आधारकीय लोकतंत्र 27 अक्तूबर 1959 को सेना द्वारा चलाया गया। जिसका प्रमुख लक्ष्य समाज के निचले तब के साथ शासन को जोड़ना तथा स्थानीय स्तर पर जन समर्थन प्राप्त करना था।
12. Hasan Akskari Rizvi, Military State and Society in Pakistan, London: Macmillan Press, 2000, Pg. 96
13. Veena Kukreja, Contemporary Pakistan: Political Process, Conflict and Crisis, New Delhi: Sage Publication, 2003, Pg. 236.
14. Lan Talbot, General Pervez Musharaf: Saviour or destroyer of Pakistan's democracy? Contemporary South Asia (2002), 11 (3), Pg. 311-328.
15. http://elections.com.pk/partymanifasto.php?ip=40
16. पी.एम.एल.एन. एचिवमेंट, http://www.pmln.org/pml-n-achievements/
17. चुनावी घोषणा पत्र से संबंधित जानकारियाँ पॉट (पाकिस्तान सीरीज वाल्यूम, न. 4, 4 जनवरी 1997 के अंक पृ० सं०– 28–29।
18. http://elections.com.pk/partymanifasto
19. Veena Kukreja and M.P. Singh (2005), Pakistan Democracy, Development and Security Issue, (New Delhi: Sage Publications,), Pg. 655
20. Veena Kukreja, Contemporary Pakistan: Political Process, Conflict and Crisis, (New Delhi: Sage Publication), 2003, Pg. 236
21. Veena Kukreja and M.P. Singh (2005), Pakistan Democracy, Development and Security Issue, (New Delhi: Sage Publications,), Pg. 157
22. Veena Kukreja, Contemporary Pakistan: Political Process, Conflict and Crisis, (New Delhi: Sage Publication), 2003, Pg. 238
23. Hasan Askari Rizvi, Pakistan in 1998: The Polity Under Pressure, Asian Survey, Vol. 39, (1), A Survey of Asia, 1998 (Jan-Feb, 1999), Pg. 81-82